

प्रेषक, बी० लाल,  
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तरांचल शासन

सेवा में,  
महाधिवक्ता,  
उत्तरांचल,  
मा० उच्च न्यायालय परिसर,  
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : देहरादून : दिनांक- २३ अक्टूबर, 2003  
विषय : मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निर्गत आदेशों के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखल न किया जाना व न ही मा० उच्च न्यायालय में चल रहे केसेज के सम्बन्ध में गम्भीरता से अनुश्रवण किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सूत्र में आवकारी विभाग के केसेज में श्री सुभाष उपाध्याय, ब्रीफ होल्डर द्वारा विभाग को गुमराह किये जाने व दिनांक-10-10-2003 के मा० उच्च न्यायालय के आदेशों की सूचना दिनांक-16-10-2003 से पूर्व शासन के प्रशासकीय विभाग को न दिये जाने पर सरकारी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही का प्रकरण शासन के विचारार्थ है ।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि मुख्य स्थायी अधिवक्ता/स्थायी अधिवक्ताओं द्वारा शासन से निर्गत आदेशों के अनुसार पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखल न किये जाने व न ही मा० उच्च न्यायालय में चल रहे केसेज के सम्बन्ध में गम्भीरता से अनुश्रवण किये जाने के विन्दु पर अपनी जाँच आख्या तत्काल शासन में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,  
( बी० लाल )  
सचिव ।